

विचार-प्रवाह... सामाजिक रूप से सचेत व्यवहार



मौसम

अधिकतम 22.0° न्यूनतम 11.0°

40243.39

2

नए वैरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

7

अक्षर पटेल के 'पंच' से सहमा न्यूजीलैंड

देहरादून, रविवार, 28 नवंबर 2021

पेज 3



29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च स्थगित

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा की मीटिंग में लिए गए फ़ैसलों की जानकारी देते हुए किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने बताया कि मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला संसद पर ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। चार दिसंबर को मोर्चा की फिर से मीटिंग होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के रूख की समीक्षा की जायेगी। किसानों के घर जाने का फ़ैसला चार दिसंबर को होने वाली मीटिंग के बाद लिया जाएगा।

मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार को चार दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर मांगें पूरी हुईं तो किसान घर चले जाएंगे। मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन ऐसे ही चलेगा। किसान

किसान आंदोलन पर 4 दिसंबर को अंतिम फैसला

अब घर लौट जाएं किसान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों को दंडनीय अपराध से मुक्त किए जाने की मांग की थी। भारत सरकार ने यह मांग को भी मान लिया है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा के बाद मैं समझता हूँ कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसानों और किसान संगठनों से निवेदन करता हूँ कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर, अपने-अपने घर लौटें।

नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि मोर्चा देखना चाहता है कि केंद्र सरकार अपना किया गया वादा संसद में पूरा करती है या नहीं। इस मीटिंग में राकेश टिकैट शामिल



सरकार को बातचीत की मेज पर आना होगा

नहीं हुए। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए।

भारतीय किसान युनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार एमएसपी, प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत और लखीमपुर

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा कि सरकार हमसे आमने-सामने बैठकर बात करे। केंद्र ने किसानों पर दर्ज मुकदमों को राज्य का विषय बताया था। इसपर किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी शासित राज्यों और रेलवे को निर्देश दें कि मुकदमे वापस लें।

हिंसा मामले पर मोर्चा के साथ बातचीत नहीं करती है तब आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने अभी जो भी घोषणाएं की हैं उससे संयुक्त किसान मोर्चा संतुष्ट नहीं है।

सोमवार को संसद तक होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित होने से दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली है। दरअसल 29 नवंबर यानी सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा।

दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आंदोलनकारियों का ट्रैक्टर मार्च को रोकना था।

इससे पहले प्रदर्शनकारी 29 नवंबर को दिल्ली में प्रवेश करने की जिद पर अड़े थे। किसान नेताओं का कहना था कि सोमवार दिल्ली की सीमाओं पर घेरना दे रहे 500 आंदोलनकारी 30 ट्रैक्टरों से संसद भवन जाएंगे। हालांकि ट्रैक्टर मार्च स्थगित होने से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा था ?

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि संसद सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए रखे जाएंगे। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीरो बजट खेती, फसल विविधीकरण, MSP को प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। कृषि सुधार कानून के विरोध में प्रदर्शन का एक साल पूरा होने पर सिंधु, टीकरी और यूपी बार्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। उग्र बार्डर पर पंचायत भी हुई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई।

संक्षिप्त समाचार

केंद्र में पराली जलाने को दंडनीय अपराध से किया मुक्त एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन के साथ एमएसपी पर किसानों की मांग पूरी हो गई है। किसान संगठनों ने किसानों द्वारा पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी। भारत सरकार ने भी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। फिर घंटे कोविड के मामले, सक्रिय केस भी हुए कम एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में कमी आई है। बीते दिन कोरोना के नए मामलों में उछाल देखा गया था, जिसके बाद मामले 10 हजार से ऊपर पहुंच गए थे, जो कि उससे पहले कई दिनों तक कम थे। अब एक बार फिर से मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

2025 तक उत्तराखण्ड बनेगा हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य

प्रधानमंत्री के विजन पर किया जा रहा उत्तराखण्ड का विकास: सीएम

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड / 25 समिति बोधिसत्व में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. के. विजयराघवन, पदमभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन मंच पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को विजन दिया है। इस विजन को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों के सुझावों

विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उत्तराखण्ड के विकास की यात्रा सबकी सामूहिक यात्रा है। राज्य के विकास के लिए जो भी जन सुझाव प्राप्त होंगे उन सुझावों पर पूरा विचार किया जायेगा। प्रदेश के समग्र विकास के लिए अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

के आधार पर आगे के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास प्राकृतिक संपदा है। इस प्राकृतिक संपदा के सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हिमालय को बचाने एवं प्रकृति के साथ संतुलन के लिए सभी को आगे आना होगा। प्राकृतिक संपदाओं एवं अन्य स्रोतों से राज्य की आय बढ़ाने की

दिशा में भी विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार से मिल रहा पूरा सहयोग: मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्य होने के नाते यहां की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। आपदा की दृष्टि से उत्तराखण्ड संवेदनशील राज्य है। किसी भी चुनौती से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार का राज्य को हर संभव सहयोग मिलता रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह देश में कोरोना वायरस पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम ने कोरोना के ताजा हालात और टीकाकरण जैसे मुद्दों की समीक्षा की। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गोवा, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा वीके पाल मौजूद रहे। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के सामने आने के बाद यह बैठक हुई।

पीएमओ के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कोरोना के नए वैरिएंट को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को भी कहा। पीएम ने

बैठक

कोरोना के नए वैरिएंट पर पीएम की शीर्ष अधिकारियों संग बैठक अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया।

कोरोना के इस नए वैरिएंट को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। भारत ने ब्रिटेन, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, समेत कई देशों को कोरोना के जोखिम वाले देशों की श्रेणी में शामिल किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उन देशों की सूची में हांगकांग और इजराइल को भी जोड़ा है जहां से यात्रियों को भारत आने पर अतिरिक्त उपायों का पालन करने की आवश्यकता होगी। जिन देशों से यात्रियों को भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा उनमें ब्राजील, बांग्लादेश बोत्सवाना, मारीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर कई देश शामिल हैं। भारत समेत विश्व के कई देश इस नए वैरिएंट को लेकर सतर्क हैं।

नए वैरिएंट को लेकर सीएम ने लोगों से की अपील

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वैरिएंट के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पूरा पालन करें। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में पूरा जन सहयोग मिला है।

राज्य सरकार द्वारा कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए

नए वैरिएंट के दृष्टिगत प्रदेशवासी कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पूरा पालन करें

सभी तैयारियां की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों का अभी दूसरा टीका नहीं लगा है, समय होते ही टीकाकरण करा लें। मास्क का उपयोग जरूर करें एवं एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव,

डीजीपी एवं सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के नए वैरिएंट की दृष्टिगत कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित कराने एवं सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं हो।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development

All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding

1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation

A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly. You tell us, we do it.

Gadoli Media Ventures

Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

Contact: